भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2537

<u>दिनांक 16 दिसम्बर,2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

चीन के साथ व्यापार घाटा

2537. श्री वी.के.श्रीकंदन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन को निर्यात में वृद्धि होने के बावजूद चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या अप्रैल से अक्तूबर, 2025 की अवधि के दौरान चीन को होने वाले निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम सात महीनों में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़कर 64 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है;

(घ) क्या इस मुद्दे के समाधान की दृष्टि से सरकार ने आयात वृद्धि की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी पैनल का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो पैनल की संरचना और इस संबंध में अब तक पैनल द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा अप्रैल-अक्टूबर 2024 में 58.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर 2025 में 63.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 10.1% की बढ़ोत्तरी है। हालांकि, व्यापार घाटा मुख्य रूप से कच्चे सामुग्रियों, इंटरमिडिएट वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के कारण है, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और असेंबली, मोबाइल फोन पार्ट्स, मशीनरी और उसके पार्ट्स, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स आदि, जिनका उपयोग परिसज्जित उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें भारत से बाहर निर्यात भी किया जाता है।चीन को भारत का निर्यात भी अप्रैल-अक्टूबर 2024 में 8.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर 2025 में 10.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 24.7% की बढ़ोत्तरी को दर्शाता है।

(घ) और (ङ): आयात और निर्यात के रुझानों पर विचार करने हेतु और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। आईएमसी की संरचना में वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय और वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। आईएमसी नियमित रूप से निर्यात और आयात की निगरानी करती है और विभिन्न हितधारकों के परामर्श से सुधारात्मक उपाय करती है।

*****